PK टाइम्स

लोक टुडे

विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्षः 12 | अंकः 305 | मूल्यः 1.00 रुपए | पृष्ठः 4 | बुधवार, 20 मई, 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

मजदूरों की आवाज नहीं दबेगी... बोलकर विधायक भाटी ने खुद पर छिड़का पेट्रोल !

39 दिनों की अनदेखी के साथ प्रशासन के अड़ियल रवैये से खफा विधायक भाटी ने किया आत्मदाह का प्रयास

पुलिस-प्रशासन की गंभीर लापरवाही | कलेक्ट्रेट के गेट तक कैसे पहुंचा पेट्रोल? रविंद्र भाटी के कदम से खड़े हुए सवाल

मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा

पेट्रोल छिड़कते ही समर्थकों ने भाटी को दबोचा, सुरक्षित ले गई कलेक्ट्रेट के अंदर

लोक टुडे। बाड़मेर

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर गिरल लिग्नाइट माइंस मजदूर आंदोलन के दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विरोध स्वरूप अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया है। इस घटना के बाद मौके पर भारी तनाव फैल गया और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित कलेक्ट्रेट के भीतर पहुंचाया। जैसे ही शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का तो समर्थकों ने कपड़े से तुरंत पेट्रोल को पोछ दिया। इसी दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी विधायक भाटी और उनके समर्थकों को धक्के मारते हुए ले गए। दरअसल, मजदूरों की मांगों को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी 500 गाड़ियों के काफिले के साथ मंगलवार दोपहर कलेक्ट्रेट की तरफ कूच किया। कलेक्ट्रेट से 1 किमी पहले पुलिस ने बसें लगा कर भाटी का काफिला रोक लिया। काफिला रोकने के बाद विधायक भाटी पैदल ही अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। समर्थकों को पुलिस ने पकड़ा तो विधायक भाटी ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। भाटी ने सोमवार को घोषणा की थी कि अगर मजदूरों की मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे मंगलवार को मजदूर आंदोलन करेंगे। इधर, इससे एक दिन पहले हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरल माइंस से लिग्नाइट परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) शुरू करने और वाहनों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसपी और शिव थानाधिकारी से बाधा उत्पन्न करने वालों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं।

सुबह का धरना शाम तक हो गया उग्र, फिर तनातनी का माहौल

बाड़मेर के गिरल क्षेत्र में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों और खनन मजदूरों को रोजगार दिलाने तथा अनुचित छंटनी के विरोध में कई दिनों से आंदोलन चल रहा था। विधायक भाटी भी कई दिनों से धरना स्थल पर ग्रामीणों के साथ डटे हुए थे और सोमवार को उन्होंने उग्र आंदोलन का ऐलान कर दिया था। सोमवार दोपहर को भाटी ने जन सभा को संबोधित करने के बाद बाड़मेर कूच किया। आंदोलन को उग्र करते हुए विधायक रविंद्र सिंह भाटी अपने हजारों समर्थकों के साथ बाड़मेर जिला मुख्यालय (कलेक्ट्रेट) पहुंचे।

सुरक्षा के लिहाज से कलेक्ट्रेट से 1 किमी दूर जैसलमेर रोड पर बीएसएफ गेट के आगे पुलिस ने अपनी 2 बसें खड़ी करके रास्ता बंद किया था। यहां से आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। भाटी को भी यही रोका गया है।

वहां प्रशासन के अड़ियल रवैये और मजदूरों की मांगें न माने जाने से नाराज होकर उन्होंने खुद पर पेट्रोल डाल दिया। घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों और सुरक्षाबलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत भाटी को काबू में किया और किसी अप्रिय घटना से बचाते हुए उन्हें कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर ले गए।

39 दिनों से धरना, किसी ने नहीं ली सुध :

राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड की गिरल में लिग्नाइट माइंस की ओर से थुंबली समेत आसपास के इलाकों में जमीन अधिग्रहण कर कोयला खनन किया जा रहा है। आरोप है कि कंपनी ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब युवाओं को नौकरी से निकाला जा रहा है। इसी से प्रभावित किसान और गांव के युवा 9 अप्रैल से गिरल गांव में धरने पर बैठे हैं। बाड़मेर जिले के गिरल लिग्नाइट माइंस में स्थानीय श्रमिकों, ड्राइवरों और ग्रामीणों का आंदोलन पिछले 39 दिन से जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ₹स्स्रुकंपनी और ठेकेदारों ने बिना किसी ठोस कारण के 100 से अधिक स्थानीय परिवारों को माइनिंग के काम से निकाल दिया है। इसके अलावा क्षेत्र में सीएसआर (ष्टस्ङ्र) के तहत कोई विकास कार्य न होने और पर्यावरण सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर भाटी पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और हीटवेव में धरने पर बैठे थे। उनकी मांग है कि 8 घंटे की ड्यूटी लागू की जाए और नौकरी के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए।

एहतियात के तौर पर जाब्ता, मुस्तैदी से टली बड़ी अनहोनी :

बाड़मेर कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा बलों और पुलिस जाब्ते की मुस्तैदी के कारण एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से टल गई। जब विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अचानक खुद पर पेट्रोल छिड़का, तब वहां तैनात भारी पुलिस बल ने तुरंत एक्शन लिया। भाटी द्वारा आत्मघाती कदम उठाते ही कलेक्ट्रेट गेट पर तैनात पुलिस अधिकारी और जवान तुरंत उनकी ओर लपके। उन्होंने माचिस या किसी भी ज्वलनशील वस्तु के उपयोग से पहले ही विधायक को सुरक्षित रूप से अपने घेरे में ले लिया।

उग्र हो रही भीड़ और तनावपूर्ण माहौल के बीच पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद विधायक भाटी को भीड़ से निकाला और कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर सुरक्षित कमरे में ले गई।

आरोप - पुलिस और प्रशासन की गंभीर लापरवाही :

बाड़मेर कलेक्ट्रेट पर हुए इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्थानीय ग्रामीणों, श्रमिकों और विधायक समर्थकों द्वारा पुलिस और प्रशासन पर बेहद गंभीर लापरवाही बरतने और असंवेदनशील रवैया अपनाने के सीधे आरोप लगे है। जिला मुख्यालय (कलेक्ट्रेट) जैसे संवेदनशील और अति-सुरक्षित क्षेत्र में हजारों की भीड़ और विधायक के पहुंचने के बावजूद सुरक्षा घेरा इतना कमजोर था कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल) सीधे कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट तक आसानी से पहुंच गया।

संवादहीनता और अड़ियल रवैया:

समर्थकों का कहना है कि जब विधायक रविंद्र सिंह भाटी सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, तब भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों ने समय रहते उनसे सीधे संवाद स्थापित नहीं किया। प्रशासन के इसी कथित अड़ियल रवैये ने जनप्रतिनिधि को इतना हताश किया कि उन्हें यह आत्मघाती कदम उठाना पड़ा।

- इंटेलिजेंस (खुफिया तंत्र) की विफलता:

स्थानीय खुफिया पुलिस इस बात का पहले से अंदाजा लगाने में पूरी तरह नाकाम रही कि लंबे समय से चल रहा यह आंदोलन बाड़मेर मुख्यालय पहुंचकर इतना विस्फोटक रूप ले सकता है। इस घटना ने सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए है।

ईंधन संकट का ग्रीन तोड़; प्रदेश में अगस्त 2026 तक दौड़ेंगी 500 हाईटेक ई-बसें

9 अत्याधुनिक डिपो भी होंगे तैयार, शासन सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया फैसला

लोक टुडे। जयपुर

राजस्थान में आम जनता के सफर को सुगम और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ईंधन खपत कम करने की अपील के बाद प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक मोड पर शिफ्ट किया जा रहा है।

शासन सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव ने समीक्षा करते हुए बताया कि पीएम ई-बस योजना और राज्य स्तर की योजनाओं के तहत अगस्त 2026 तक प्रदेश में 500 ई-बसें उपलब्ध करा दी जाएंगी।

इन बसों के सुचारू संचालन के लिए राजस्थान में 9 अत्याधुनिक ई-बस डिपो का निर्माण भी किया जा रहा है। यह ई-बसें मुख्य रूप से जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा और अलवर जैसे बड़े शहरों में चलेंगी। इसके साथ ही, राजस्थान रोडवेज के बेड़े को मजबूत करने के लिए इस साल अगस्त तक 144 नई ब्लू-लाइन बसें और 30 एसी स्लीपर बसें भी सड़कों पर उतरेंगी। इस फैसले के बाद प्रदेश में न केवल प्रदूषण घटेगा, बल्कि ईंधन की किल्लत या संकट होने पर भी आम यात्रियों का सफर कभी नहीं रुकेगा।

8 शहरों में चलेगी ये बसें :

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना एवं राज्य स्तर की योजनाओं के तहत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में इन 500 ई-बसों का संचालन किया जाएगा। इनमें जयपुर में सबसे अधिक 150 ई-बसें राजधानी की सड़कों पर दौड़ेंगी। इनके अलावा जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा और अलवर में 50-50 ई-बसें आवंटित की गई हैं।

अब होगा इको-फ्रेंडली परिवहन :

राजस्थान में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय किसी अचानक आए संकट की वजह से नहीं, बल्कि राज्य के बड़े शहरों में तेजी से बदलते हालातों, बढ़ते शहरीकरण और परिवहन की गंभीर कमियों को दूर करने के लिए लिया गया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के अनुसार इन बसों को अगस्त 2026 तक सड़कों पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार को यह बड़ा कदम इन मुख्य हालातों और कारणों की वजह से उठाना पड़ रहा है।

शहरों में तेजी से बढ़ता यातायात दबाव और शहरीकरण :

राजस्थान के प्रमुख शहर जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर बहुत तेजी से फैल रहे हैं। बाहरी कॉलोनियों और नए विकसित क्षेत्रों में छात्र, नौकरीपेशा लोग और आम जनता रोजाना सफर करती है। मौजूदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट (जैसे जयपुर मेट्रो या पुरानी बसें) पूरे शहर को कवर नहीं कर पा रही हैं, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव और निजी वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

वायु और ध्वनि प्रदूषण का खतरनाक स्तर :

शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक डीजल और पेट्रोल वाहनों के कारण प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। पर्यावरण को बचाने, शहरों की हवा को शुद्ध करने और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार को 'इको-फ्रेंडली' (पर्यावरण अनुकूल) परिवहन का सहारा लेना पड़ रहा है।

महंगे ईंधन (डीजल/पेट्रोल) की मार और आर्थिक बचत :

पारंपरिक बसों को चलाने में ईंधन (फ्यूल) पर भारी खर्च होता है, जिससे परिवहन निगमों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। इलेक्ट्रिक बसों के आने से ईंधन की भारी बचत होगी और संचालन की लागत काफी कम हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा सरकार और आम जनता दोनों को मिलेगा

सम्पादकीय

न्यायाधीशों का संख्याबल

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह अध्यादेश जारी किया, उससे यह पता चलता है कि वह शीर्ष कोर्ट में शीघ्र ही न्यायाधीशों की संख्या बढ़ते हुए देखना चाहती है। अब मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 38 हो जाएगी। निश्चित रूप से इससे सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने और न्यायिक प्रणाली में तेजी लाने में सहायता मिलेगी।

उम्मीद की जाती है कि इसके चलते सुप्रीम कोर्ट से लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा, लेकिन प्रश्न यह है कि उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में स्थिति कैसे और कब बदलेगी? आवश्यकता ऐसे उपाय करने की भी है कि उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में भी लंबित मुकदमों का बोझ कम हो और लोगों को समय पर न्याय सुलभ हो। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला स्तर तक की अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या लगभग पांच करोड़ पहुंच गई है। न तो लंबित मुकदमों का बोझ कम हो रहा है और न ही लोगों को समय पर न्याय मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि सामान्य मामलों का निपटारा होने में भी वर्षों और कई बार तो दशकों लग जाते हैं। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि न्याय में देरी एक तरह का अन्याय ही है। सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, इनमें केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से ही बात बनने वाली नहीं है। यदि समय पर न्याय देना है तो हर स्तर पर न्यायपालिका को पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर से लैस भी करना होगा। न्याय में देरी का एक कारण न्यायाधीशों की कमी ही नहीं, बल्कि संसाधनों का अभाव भी है। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों में भी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने पर गंभीरता से विचार इसलिए किया जाना चाहिए, क्योंकि अपने देश में प्रति दस लाख जनसंख्या पर लगभग 22 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं। इसके विपरीत विकसित देशों में प्रति दस लाख आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या सौ से अधिक है। दशकों पहले विधि आयोग ने त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रति दस लाख आबादी पर कम से कम 50 न्यायाधीशों की नियुक्ति की आवश्यकता जताई थी। कोई नहीं जानता कि इस आवश्यकता की पूर्ति क्यों नहीं की जा पा रही है? समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए यह भी आवश्यक है कि न्यायिक प्रक्रिया के तौर-तरीके बदलें। इसके अतिरिक्त, कार्यपालिका अपने लोगों के खिलाफ मुकदमे करने की प्रवृत्ति का परित्याग करे। यदि यह सब नहीं किया जाता तो तारीख पर तारीख का सिलसिला थमने वाला नहीं है।

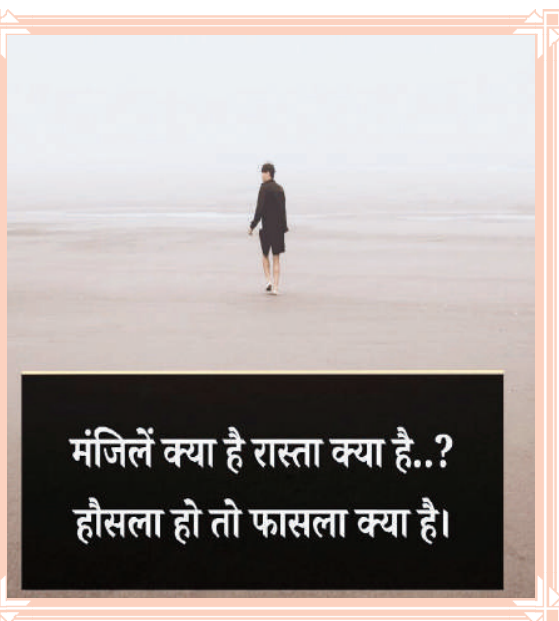

मुख्यमंत्रियों के चुनाव हारने की परंपरा

सत्ताधारी मुख्यमंत्री का अपनी ही विधानसभा सीट गंवा देना भारतीय राजनीति का एक रोचक और जटिल पहलू है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक संदर्भों से लेकर हालिया चुनावी उथल-पुथल तक, यह सिलसिला लोकतंत्र की एक ऐसी गाथा सुनाता है जहां जनता की खामोशी सत्ता के अहंकार से कहीं अधिक शक्तिशाली सिद्ध होती है। भारतीय संसदीय इतिहास में मुख्यमंत्रियों के हारने की परंपरा पुरानी है, जो यह दर्शाती है कि यहां की लोकतांत्रिक जड़ें व्यक्ति विशेष के कद से हमेशा गहरी रही हैं। इसकी शुरुआत 1971 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह की मनीराम सीट पर हुई हार से हुई थी, जिसने देश को पहली बार यह अहसास कराया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी चुनावी जीत की गारंटी नहीं है। इसके बाद समय-समय पर बड़े नाम इस सूची में जुड़ते गए।

शिबू सोरेन का 2009 के उपचुनाव में तमाड़ सीट से हारना एक बड़े राजनीतिक संकट के रूप में उभरा, क्योंकि वह निर्वाचित हुए बिना मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे। इसी तरह बंगाल में 34 वर्षों के वामपंथी शासन के पतन की सबसे बड़ी मुहर मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की 2011 में जाधवपुर सीट पर हुई हार थी। उत्तराखंड की भूमि पर भी जनता ने बार-बार यह संदेश दिया है। 2012 में भुवन चंद्र खंडूड़ी का कोटद्वार से हारना और 2017 में हरीश

रावत का हरिद्वार ग्रामीण एवं किच्छा जैसी दोनों सीटों से पराजित होना इसी लोकतांत्रिक चेतना का प्रतीक है। 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार से पराजित हुए, जबकि उनकी पार्टी भाजपा राज्य में स्पष्ट बहुमत के साथ वापसी कर रही थी। ये रुझान दर्शाते हैं कि सत्ता की चमक कभी भी मतदाता की मूल अपेक्षाओं और उसके स्वाभिमान के सामने टिक नहीं पाती।

किसी मुख्यमंत्री की हार के पीछे अक्सर सबसे बड़ा कारण उनका अति-आत्मविश्वास और सत्ता का अहंकार होता है। जब कोई नेता लंबे समय तक सत्ता में रहता है या भारी बहुमत से जीतता है तो अक्सर वह जनता की नब्ज टटोलने के बजाय अपनी इच्छाएं जनता पर थोपना शुरू कर देता है। जनता की भावनाओं को समझने के बजाय जब अपनी मनमानियों को जनमानस पर लादने की कोशिश करते हैं तो वहीं से उनके पतन की पटकथा लिखी जाती है। 2017 में हिमाचल के प्रेम कुमार धूमल की सुजानपुर में हार हो या गोवा के लक्ष्मीकांत पारसेकर की मंड्रेम में शिकस्त के पीछे जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और सत्ता का बढ़ता हुआ केंद्रीकरण था। जब जनता को यह लगने लगता है कि उनका सेवक अब उनका शासक बनने की कोशिश कर रहा है तो वह मतदान केंद्र पर चुपचाप अपनी ताकत दिखा देती है।

हाल के वर्षों में, विशेषकर 2021 से 2026 के मध्य, चुनाव में मुख्यमंत्रियों की हार के पैटर्न ने भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। बंगाल के 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी से मात खा गईं। ममता बनर्जी ने उसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, लेकिन जनता ने यह संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष को अपनी जागीर नहीं समझ सकता।

पंजाब में 2022 के चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी का अपनी दोनों सीटों, चमकौर साहिब और भदौड़ से हारना सत्ता के प्रति जनता के तीव्र मोहभंग का परिणाम था। 2024 में ओडिशा के अजेय माने जाने वाले नवीन पटनायक का कांटाबांजी सीट से हारना और 24 साल के शासन का अंत होना, इस बात का प्रमाण है कि जनता एक समय के बाद बदलाव और नई ऊर्जा चाहती है।

2026 के ताजा चुनावी परिणामों ने इस फेहरिस्त में सबसे चौंकाने वाले अध्याय जोड़े हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहते एमके स्टालिन का अपनी अभेद्य मानी जाने वाली कोलाथुर सीट पर एक नवोदित दल टीवीके के प्रत्याशी से लगभग 9,000 वोटों से हारना यह दर्शाता है कि दक्षिण की राजनीति में भी द्रविड़ किले में दरारें पड़ चुकी हैं। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर हार और सिक्किम में पवन कुमार चामलिंग की पूर्व में पराजय यह साबित करती हैं कि चेहरा कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह काम और व्यवहार का विकल्प नहीं हो सकता। कर्नाटक में सिद्दरमैया की चामुंडेश्वरी में हार भी इसी अहंकार की बलि चढ़ने का उदाहरण थी।

मुख्यमंत्रियों की हार को देखते हुए बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह निजी असफलता है या व्यापक राजनीतिक संकेत? वस्तुत: देखा जाए तो मुख्यमंत्रियों की हार के सवाल का उत्तर एक से अधिक आयामों में छिपा है। कई बार स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण, उम्मीदवार चयन में हुई चूक, गुटबाजी या विपक्षी उम्मीदवार की मजबूत अपील इसका कारण बनती है।

यह राजनीतिक दलों के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि शीर्ष नेतृत्व की लोकप्रियता के भरोसे अकेले चुनाव नहीं जीते जा सकते। जमीनी संगठन, स्थानीय मुद्दों की समझ और उम्मीदवार की छवि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वहीं यह सत्ता विरोधी आक्रोश भी है, क्योंकि यह शासकों को चेतावनी देता है कि वे जनता की भावनाओं को हल्के में न लें। जब सत्ता के गलियारों में बैठे लोग जनता का मन टटोलना बंद कर देते हैं और अपनी नीतियां या अपनी सनक को उन पर थोपते हैं तो जनता का गुस्सा शांत, लेकिन प्रभावी ढंग से फूटता है।

संकट के समांतर : आर्थिक महाशक्तियों को बाकी दुनिया की कोई फिक्र नहीं

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे से यह उम्मीद की जा रही थी कि पश्चिम एशिया में संघर्ष का कोई हल निकलेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर गहरा रहे संकट से राहत मिलेगी। मगर दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई वार्ता के नतीजों से यह साफ है कि विश्व की आर्थिक महाशक्तियों को बाकी दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। खबरों के मुताबिक, बैठक द्विपक्षीय मसलों पर ही केंद्रित रही और ट्रंप ने इसे 'जी-2' देशों का सम्मेलन बताया, जिसमें दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक समझौते हुए। सवाल है कि खुद को दुनिया के सबसे ताकतवर बताने वाले देशों की क्या वैश्विक समुदाय के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्या उनकी यह ताकत सिर्फ निहित स्वार्थों तक ही सीमित है?

पिछले कुछ वर्षों से विश्व के आर्थिक हितों को देखने के अमेरिका के नजरिए में बदलाव साफ नजर आ रहा है। अब यह साझा उदार मूल्यों पर नहीं, बल्कि महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्रों पर केंद्रित होता दिख रहा है। ऐसे में सवाल यह नहीं है कि अमेरिका और चीन परस्पर सहयोग कर सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि उनके बीच तालमेल संभव हो सका, तो वह किस तरह की वैश्विक व्यवस्था तैयार करेगा।

दो देशों का समूह यानी 'जी-2' शब्द वर्ष

2005 में अमेरिका के एक प्रमुख अर्थशास्त्री ने गढ़ा था। उनका विचार था कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच मजबूत साझेदारी होनी चाहिए। इस विचार का उद्देश्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह 'जी-20' को और मजबूत करना था। तब वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के लिए 'जी-20' की रणनीति के तहत अमेरिका ने शुरुआती दौर में 787 अरब डालर, जबकि चीन ने 586 अरब डालर का प्रोत्साहन पैकेज दिया था। इससे दुनिया को बड़े आर्थिक संकट से बचाने में मदद मिली। मगर पश्चिम एशिया में संघर्ष से उपजे वैश्विक संकट के बीच हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई वार्ता में वैश्विक चिंताओं के बजाय परस्पर हितों की एक नई तस्वीर उभरकर सामने आई है। दोनों देशों के बीच बोइंग विमानों की खरीद समेत कई अहम व्यापारिक समझौते हुए हैं। यानी अब अमेरिका-चीन सहयोग का मतलब यह नहीं है कि उससे दुनिया के बाकी देशों के लिए सकारात्मक माहौल बनेगा, बल्कि यह एक ऐसे निजी समझौते की तरह दिखाई देता है, जिसमें दो महाशक्तियां सिर्फ अपने हित साध रही हैं।

गौरतलब है कि होर्मुज जलमार्ग के बाधित होने से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा समेत कई आवश्यक वस्तुओं का संकट पैदा हो गया है। अमेरिका और ईरान के अड़ियल रवैये की वजह से शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिसका असर तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इसमें दोराय नहीं कि शांति वार्ता के लिए एक प्रभावी मध्यस्थ की जरूरत है और चीन इसमें अहम भूमिका निभा सकता है।

मगर अमेरिका और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात में इस मसले को तवज्जो नहीं देने को किस रूप में देखा जाएगा। खबरों के मुताबिक, इस दौरान ताइवान का मसला जरूर उठा और इस पर चीन ने अमेरिका को चेताते हुए कहा कि यदि इस मुद्दे को सही ढंग से नहीं संभाला गया, तो दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है।

समस्या आई है तो जाएगी भी

जीवन में कठिनाइयां तो आती ही रहती हैं इसलिए उनका इतना टेंशन लेना नहीं चाहिए। आजकल एक नयी कठिनाई आ गई है, जो कि पड़ोस में बना रहे मकान से है। मजदूर लोग सुबह 6:00 बजे से ही काम करने लग जाते हैं, जो कि शाम को 7:00 बजे तक चलता है, जबकि बेंगलुरु में नियम के अनुसार मकान कंस्ट्रक्शन का काम सुबह 8:00 बजे से शाम के 7 :00 बजे तक ही हो सकता है यह सोसायटी का भी नियम है। हमने अपनी सोसायटी में मैनेजमेंट कमेटी को कहा कि आप उन पड़ोस की मैनेजमेंट कमेटी से बात करें और उन्हें बताएं की सुबह 6 :00 बजे से काम करने से नींद पूरी नहीं होती है।

एक दिन गुस्से में आकर मैं छत पर जाकर उन पर चिल्ला भी आया, पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि केवल मुझे ही समस्या है। मेरे पड़ोस में और तीन मकान है जिनके यहां भी उतनी ही आवाज आती होंगी जितनी मेरे यहां। पता नहीं क्यों वे लोग शिकायत नहीं करते और न ही उस सोसायटी के अन्य पड़ोसी शिकायत करते हैं। जबकि यहां सोसायटी में अधिकतर लोग अमेरिका यूरोप रहकर आए हुए हैं और संभ्रांत हैं परंतु भारत में आकर सब ठेठ भारतीय हो जाते हैं और दूसरे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। यही काम अगर वे अमेरिका या यूरोप में कर लें तो एकदम से पुलिस को लोग बुला लेंगे और काम बंद हो जाएगा। परंतु यहां तो पुलिस को बुलाना भी किसी सिर दर्द से कम नहीं। पुलिस की आम जनता में जो छवि रही है कि पुलिस पैसे के बिना काम नहीं करती और हम नौकरी-पेशा लोग नौकरी करेंगे या फिर थाने के चक्कर लगाएंगे।

मैं, लगभग रोज सुबह ही 6 बजे जैसे ही काम शुरू होता है, वैसे ही उस सोसायटी के सिक्योरिटी को फोन लगाता हूं, रोज आते-जाते हुए उन्हें कहता भी हूं, परंतु वे लोग भी लगता है कि रोकने में अक्षम हैं, ऐसा लगता है कि उनको भी यह बात बहुत छोटी लगती है।

जिनके मकान बन रहा है वे तो यहां रहते नहीं है तो हो सकता है उन्हें परेशानी समझ में न आ रही हो और आ भी रही हो, तो वे तो यही चाहेंगे कि काम तेजी से चलता रहे, जिससे कम वक्त में मकान बनाकर तैयार हो जाए। लिखने का मकसद केवल इतना है कि सारे कार्य केवल सरकार और कानून के सहारे नहीं होते, कुछ कार्यों को खुद के अनुशासन और नियमों को पालने से भी समस्या का निराकरण किया जा सकता है। अंत में बात तो यह है कि कोई समस्या आई है तो वह जाएगी भी, इसलिए सब्र जरूरी है।

सत्ता के साथ साख भी गंवाई

वैसे तो हार-जीत एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं, लेकिन अगर आपके हिस्से अक्सर एक ही पहलू आए तो गंभीर आत्मविश्लेषण की जरूरत है। हालिया विधानसभा चुनाव परिणामों ने इस पहलू को फिर से रेखांकित किया है। असम में भाजपा की हैटट्रिक को लेकर शायद कांग्रेस को भी संदेह नहीं रहा होगा। खासकर 2023 के परिसीमन के बाद सामाजिक समीकरणों पर भाजपा की पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि वहां उसकी सत्ता को हिलाना फिलहाल तो आसान नहीं है।

अपनी आक्रामक भाषा और राजनीतिक प्रबंधन से भी अपनी उपयोगिता साबित कर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भाजपा आलाकमान के लाड़ले बन गए हैं। न सिर्फ असम, बल्कि समूचे पूर्वोत्तर में भाजपाई सत्ता विस्तार में हिमंत की अहम भूमिका रही। इसे देखते हुए क्या कांग्रेस को ऐसे उपयोगी नेता को गंवाने पर कोई अफसोस होता है या नहीं?

यह भी न भूला जाए कि कांग्रेस सरकारों में वरिष्ठ मंत्री रहे हिमंत ने राहुल गांधी के व्यवहार से खफा होकर ही कांग्रेस छोड़ी थी। राहुल गांधी की टिप्पणियों से तो नहीं लगता कि ऐसे उपयोगी और जनाधार वाले नेताओं के अलगाव पर कांग्रेस में कोई आत्मचिंतन चल रहा है। बंगाल की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी की सत्ता का 15 साल पुराना मजबूत किला ध्वस्त हो गया। देखा जाए तो ममता और उन्हें सत्ता से अपदस्थ करने में अहम भूमिका निभाने वाले सुवेंदु अधिकारी दोनों ही मूलत: कांग्रेसी हैं।

पांचवीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने एन. रंगासामी भी पुराने कांग्रेसी ही हैं, जिन्होंने अलग क्षेत्रीय पार्टी बना कर भाजपा से गठबंधन में दूसरी बार जनादेश हासिल किया है। यह कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक समझ और प्रबंधन के फर्क को भी रेखांकित करता है। कांग्रेस जहां ऐसे उपयोगी नेताओं को मान-सम्मान नहीं दे पाती, वहीं भाजपा उन्हें दूसरे दलों से भी लाकर अपने यहां समाहित कर लेती है। इस बार अकेले बहुमत मिलने के बावजूद भाजपा ने असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट जैसे मित्र दलों को संक्षिप्त मंत्रिमंडल गठन में भी स्थान दिया है, जबकि कांग्रेस के मित्र दलों की नाराजगी असम में भी मुखर होने लगी है।

कांग्रेस बंगाल में लगभग सभी सीटों पर जीतने के बाद दो पर जीत हासिल करने में भी सफल रही, लेकिन इससे विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआइए की साख और भविष्य पर भी सवाल उठने लग गए। बेशक इसके लिए ममता बनर्जी की जिद भी उतनी ही जिम्मेदार रही, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव और हाल के विधानसभा चुनाव में भी सहयोगी दलों को कोई भाव नहीं दिया। आइएनडीआइए का यह विरोधाभास भी किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर साथ होते हुए भी केरलम में कांग्रेस और वाम मोर्चा आमने-सामने होते हैं।

विशेष आलेख /राशिफल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की विदेश यात्रा के कूटनीतिक निहितार्थ भारत के लिए महत्वपूर्ण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच देशों के हालिया विदेश दौरे के कई बड़े कूटनीतिक, आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक मायने हैं। क्योंकि मई 2026 में उनका यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब दुनिया ऊर्जा संकट, ईरान युद्ध, सप्लाई चेन अस्थिरता और नए वैश्विक ध्रुवीकरण से गुजर रही है। लिहाजा, पीएम मोदी का यह विदेश दौरा केवल औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक शक्ति संतुलन, निवेश आकर्षण, तकनीकी साझेदारी, और भारत की उभरती महाशक्ति छवि को मजबूत करने की बहुस्तरीय रणनीतिक कवायद माना जा रहा है। पहला, ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि भारत दुनिया का बड़ा तेल आयातक देश है। ईरान संकट और पश्चिम एशिया में तनाव के कारण तेल कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे समय में यूएई दौरा भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है। लिहाजा भारत और यूएई के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण, एलपीजी सप्लाई, ऊर्जा निवेश, समुद्री सुरक्षा जैसे अहम समझौते हुए हैं। इससे संकेत मिलता है कि भारत भविष्य के किसी बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट के लिए खुद को सुरक्षित करना चाहता है। दूसरा, पश्चिम एशिया में भारत की रणनीतिक पकड़ बढ़ रही है, क्योंकि यूएई ने पीएम मोदी का असाधारण स्वागत किया- एफ-16 एस्कॉर्ट और राष्ट्रपति स्तर की अगवानी- यह दिखाता है कि भारत अब केवल तेल खरीदने वाला देश नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार बन चुका है। इसके मायने ये

निकलते हैं कि पाकिस्तान की पारंपरिक खाड़ी पकड़ कमजोर होगी और भारत की अरब देशों में स्वीकार्यता बढ़ती जाएगी। इससे रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग का विस्तार भी होगा।

तीसरा, यूरोप के साथ नई तकनीकी साझेदारी विकसित होगी, क्योंकि नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का चयन बहुत रणनीतिक माना जा रहा है। चूंकि इन देशों से भारत सेमीकंडक्टर तकनीक, हरित ऊर्जा, जल प्रबंधन, एआई और रक्षा तकनीक और आर्कटिक एवं समुद्री सहयोग को मजबूत करना चाहता है। विशेषकर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है। इसलिए इस पहल के अपने रणनीतिक मायने हैं।

चौथा, चीन और अमेरिका दोनों को संतुलित संदेश देने के लिए पीएम मोदी का यह दौरा मल्टी-अलाइनमेंट नीति का हिस्सा भी है, इससे अमेरिका के साथ साझेदारी, रूस से संबंध, अरब देशों से सामरिक निकटता, यूरोप के साथ तकनीकी सहयोग, चीन के प्रभाव का संतुलन बढ़ेगा। चूंकि भारत यह संदेश देना चाहता है कि वह किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बल्कि स्वतंत्र वैश्विक शक्ति है।

पांचवां, भारत को निवेश हब बनाने की कोशिश यूएई द्वारा भारत में 5 अरब डॉलर निवेश की घोषणा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ सकता है। यह मेक इन इंडिया और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की रणनीति से जुड़ा है।

छठा, घरेलू राजनीति के संकेत के नजरिए से दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ पीएम मोदी जनता से ईंधन बचाने, विदेशी यात्राएं कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद बड़े वैश्विक दौरे कर रहे हैं।

क्या कहते है आपके सितारें....?

मेष आज आप पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर घरेलू मामलों के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। घर को नए सिरे से योजनाबद्ध करके आप उसे एक नया स्वरूप देंगे।

सिंह आपका आज का दिन आनंद और खुशी के पलों में व्यतीत होगा। आप नया कार्य शुरू कर सकेंगे। सहोदरों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। भाग्य में वृद्धि हो सकती है।

धनु आज आप विदेश में बसने वाले मित्रों या स्नेहीजनों के अच्छे समाचार पाकर आनंद अनुभव कर सकेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है।

वृषभ आज का दिन मनोरंजन और मौज-मस्ती में व्यतीत होगा। परिजनों या मित्रों के साथ घूमने या फिल्म देखने जाने की संभावना है। आप अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे।

कन्या आपके घर में आनंद का वातावरण रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका समय आनंद और उत्साह में व्यतीत होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेग।

मकर आपको किसी का पक्ष लेने से बचना चाहिए। किसी के साथ रुपये का लेन-देन नहीं करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव हो सकता है।

मिथुन आपका आज का दिन मिश्र फलदायी होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद या मनमुटाव होने की संभावना है। आज आपका मनोबल दृढ़ न होने के कारण निर्णय लेने में तकलीफ होगी।

तुला आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है। नौकरी में आपकी आय बढ़ेगी। आपके मित्रों और बुजुर्गों से भी आपको लाभ हो सकता है। नए मित्र बनाएंगे और यह मैत्री आगे चलकर लाभदायक साबित होगी।

कुंभ आपके निर्धारित कार्य पूरे होंगे। ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में आनंद छाया रहेगा। आप तन-मन से स्वस्थ रहेंगे।

कर्क आज अत्यधिक भावुकता आपके मन को आर्द्र बनाएगी। महिला और माताजी से संबंधित चिंताएं रहा करेंगी। प्रवास के लिए उचित समय नहीं है।

वृश्चिक आपको अपने मिजाज को काबू में रखना पड़ेगा, ताकि कोई समस्या न हो। बीमार व्यक्ति आज कोई नई उपचार पद्धति न आजमाएं।

मीन आज संतान सम्बंधी मामलों को लेकर चिंता रहेगी। पेट संबंधी परेशानियां होंगी। विद्याध्ययन के लिए समय अनुकूल नहीं है।

पहली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक

अमित शाह बोले- आदिवासी महिलाओं को गाय-भैंस देंगे

कहा- बस्तर में डेयरी नेटवर्क बनेगा, नक्सल खात्मे का टारगेट पूरा, कांग्रेस सरकार ने मदद नहीं की

जगदलपुर(एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद के खात्मे का टारगेट हासिल कर लिया गया। शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस (भूपेश) सरकार से उन्हें नक्सल उन्मूलन में सहयोग नहीं मिला।

बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद 70 कैंपों में से लगभग एक-तिहाई कैंपों को 'वीर शहीद गुंडाधर सेवा डेरा' के रूप में विकसित किया जाएगा। गृहमंत्री ने आगे कहा कि हर आदिवासी महिला को पशुपालन से जोड़ने की योजना है। सरकार महिलाओं को गाय और भैंस उपलब्ध कराएगी। 6 महीने में बस्तर में बड़ा डेयरी नेटवर्क बनेगा।

बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जगदलपुर में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। बैठक में राज्यों के विकास के साथ-साथ गंभीर सामाजिक और सुरक्षा मुद्दों पर कड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में चारों राज्यों में अपराध नियंत्रण, विशेषकर महिलाओं के उत्पीड़न और रेप जैसे मामलों पर जल्द फैसले लेने पर चर्चा की गई।

राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की बैठक में तय हुई कार्यक्रमों की रूपरेखा

राजस्थान विधान सभा के 75वें वर्ष में होंगे चार बड़े कार्यक्रमःदेवनानी

जयपुर(नि.सं.)। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा के 75वें वर्ष में चार बड़े कार्यक्रम होंगे। एक वर्ष तक चलने वाले अमृत महोत्सव के तहत होने वाले समारोह ऐतिहासिक और गौरवशाली होंगे। यह उत्सव विधायिका को समर्पित होगा। समारोह की विशिष्टता के अनुरूप देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रमों में संसदीय और संविधान विशेषज्ञों के विशेष सत्र होंगे। सभी समारोहों में राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण आमंत्रित होंगे। देवनानी ने कहा कि यह अमृत महोत्सव लोकतंत्र के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को एक सूत्र में जोड़ने वाला ऐसा राष्ट्रीय आयोजन होगा, जिसमें अनुभव, परंपरा, नवाचार, महिला, युवा ऊर्जा और जनविश्वास एक साथ दिखाई देंगे। यह आयोजन भारतीय संसदीय लोकतंत्र की गौरवशाली आत्मा का उत्सव होगा। स्पीकर देवनानी मंगलवार को विधान सभा में राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ राजस्थान शाखा की कार्यकारिणी समिति की बैठक में राजस्थान विधान सभा के 75वें वर्ष में आयोजित किये जाने वाले समारोहों की चर्चा कर रहे थे। स्पीकर श्री देवनानी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष एवं राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ राजस्थान शाखा के उपाध्यक्ष टीकाराम जूली, संघ के सचिव एवं विधायक संदीप शर्मा, कार्यकारिणी समिति के सदस्य विधायक श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्री श्रीचन्द कृपलानी, शौभा चौहान, हरिमोहन शर्मा, हमीर सिंह भायल और देवी सिंह शेखावत सहित विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री भारत भूषण शर्मा भी मौजूद रहे।

पूर्व एवं वर्तमान विधायकों का सम्मेलन

बैठक में तय किया गया कि जुलाई माह में होने वाला प्रथम कार्यक्रम राजस्थान की पहली से सोलहवीं विधान सभा तक के पूर्व एवं वर्तमान सदस्यों का विशाल सम्मलेन होगा, जिसमें लोकतंत्र की ऐतिहासिक यात्रा को जीवंत किया जाएगा। महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट कानूनों, सामाजिक परिवर्तनकारी निर्णयों और संसदीय परंपराओं की समीक्षा की जाएगी।

केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा

डोटासरा बोले- क्या फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है ?

फ्यूल बचाने की नौटंकी कर रहे मंत्री, पीसीसी चीफ ने कहा- मदन राठौड़ की जल्द पर्ची बदलेगी

जयपुर(नि.सं.)। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा- पेट्रोल-डीजल की किल्लत है, रोज दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई चरम पर है। उद्योग बंद हो चुके हैं। आने वाले दिनों में ही हालात ऐसे ही रहे तो 10-15 दिन के अंदर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगने के हालात हो जाएंगे। डोटासरा ने कहा- क्या देश में फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है? क्योंकि देश की बिगड़ती स्थिति पीएम मोदी के हाथ से निकलती जा रही है। फिर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, पेट्रोल पंपों पर तेल भरवाने की कैप, उद्योग धंधों पर ताला, रुपए में ऐतिहासिक गिरावट, चरम पर महंगाई और मंदी की आहट, हालात भयावह होते जा रहे हैं। डोटासरा ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पर्ची जल्द बदलने वाली है।

पीएम को दिखाने के लिए फ्यूल बचाने की नौटंकी कर रहे मंत्री

डोटासरा ने कहा- पीएम मोदी को राजी करने के लिए राजस्थान में नौटंकी की जा रही है। परिवहन मंत्री खाली बस मंगवा कर जा रहे हैं। अगर आप अपनी-अपनी गाड़ी में जाते तो 12 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती, आप तीन का एवरेज देने वाली बस को बुलाकर और कार्यकर्ताओं को चढ़ा कर दिखा रहे हो। कोई मंत्री स्कूटी में जा रहा है, कोई रेल की टिकट करवा कर जा रहा है।

न्यूज ब्रीफ

रोडवेज से जा रही महिला से 2 किलो अफीम मिली

हैंड बैग में रखी हुई थी, कीमत 5 लाख रुपए

भरतपुर(वि.सं.)। भरतपुर की खेड़ली मोड़ थाना पुलिस ने एक महिला से 2 किलो अफीम बरामद की है। महिला धौलपुर रोडवेज से जयपुर की तरफ जा रही थी। पुलिस को मुखबिर के जरिए महिला के बारे में जानकारी मिली थी। महिला बालोतरा जिले के धौरीमन्ना इलाके की रहने वाली है। जिसे पूछताछ की जा रही है।

रोडवेज बस से अफीम लेकर जा रही थी महिला

खेड़ली मोड़ थाना अधिकारी राजेश कसाना ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक महिला भरतपुर से जयपुर जाने वाले धौलपुर डिपो बस में अफीम लेकर जा रही है।

जिसके बाद थाने पर नाकाबंदी की गई। बस को रुकवाया गया। सभी यात्रियों के बैग की तलाशी ली गई।

अजमेर में आएंगे राहुल गांधी और खड़गे

पुष्कर में होगा कांग्रेस का 10 दिवसीय चिंतन शिविर; कई मुद्दों पर होगा मंथन

अजमेर (वि.सं.)। अजमेर में कांग्रेस का चिंतन और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने, चुनावी रणनीति तैयार करने और जनहित के मुद्दों पर शिविर में मंथन किया जाएगा। शिविर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दो दिन तक मौजूद रहेंगे। इनके अलावा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अलग-अलग सत्रों में हिस्सा लेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में 23 मई से 1 जून तक 10 दिवसीय यह शिविर पुष्कर में आयोजित होगा। शिविर की मेजबानी अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी करेगी।

दीया कुमारी श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में आयोजित 15वें श्री गणेश पाटोत्सव कार्यक्रम में हुई सम्मिलित

जयपुर में दिल्ली रोड स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में आयोजित 15वें श्री गणेश पाटोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन हमारी सनातन परंपराओं, सामाजिक समरसता एवं आध्यात्मिक चेतना को और अधिक सशक्त बनाने का कार्य करते हैं।

मुख्य सचिव ने की ई-परिवहन सेवाओं के विस्तार और प्रगति की समीक्षा

मुख्यमंत्री की ईंधन खपत कम करने की अपील पर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन में ई-बसों को बढ़ावा

जयपुर(नि.सं.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ईंधन खपत कम करने एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की अपील के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में पीएम ई-बस योजना एवं राज्य स्तर पर स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत अगस्त 2026 तक प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के लिए 500 ई-बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन बसों के संचालन के लिए प्रदेश में 9 अत्याधुनिक ई-बस डिपो का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं राज्य में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में भी विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत इस वर्ष अगस्त माह तक 144 ब्लू-लाइन बसें एवं 30 एसी स्लीपर बसें उपलब्ध हो जाएंगी। इससे प्रदेश में रोडवेज सेवाओं को मजबूती मिलेगी तथा लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय मे आयोजित बैठक में ई-परिवहन सेवाओं के विस्तार और प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने बैठक में स्वायत्त शासन विभाग, परिवहन विभाग, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ ई-परिवहन विस्तार योजनाओं पर चर्चा करते हुए प्रदेश में ई-बसों एवं बसों के क्रय की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर, सुरक्षित एवं सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए संवेदनशील हैं।

मेनका गांधी का बयान

आवार कुत्तों के लिए हर जिलें एक एबीसी शेल्टर खुलना जरूरी: मेनका गांधी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने देश में डॉग बाइट (कुत्तों के काटने) की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाने के अपने फैसले को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें डॉग लवर्स की ओर से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के पूर्व आदेश में बदलाव की मांग की गई थी। वहीं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। मेनका गांधी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हार मान ली है। उन्होंने जो नवंबर 2022 को ऑर्डर दिया था, उसमें उन्होंने शेल्टर बनाने और एबीसी शेल्टर बनाने के आदेश के साथ राज्यों के सचिवों को बुलाकर खास हिदायत भी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर शेल्टर नहीं बनेंगे तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, कोई शेल्टर नहीं बना। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब आप हाई कोर्ट चले जाइए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 780 जिले हैं तो 780 एबीसी शेल्टर नहीं बनाएं, लेकिन एक भी नहीं बना।

भारत में आईएसआई की ड्रोन के जरिए नकली नोट भेजने की साजिश, भारतीय एजेंसियां अलर्ट

नई दिल्ली(एजेंसी)। एजेंसियों की जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान की आईएसआई और उसके मददगार भारत में बड़े पैमाने पर नकली नोट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता के इलाके त्रिपुरा-बांग्लादेश बॉर्डर और पंजाब हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर नकली नोट भारत में पहुंचाने के लिए कूरि?यर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पंजाब में ड्रोन के जरिए यह खतरा तेजी से बढ़ रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि नकली भारतीय नोटों को लेकर आईएसआई ने दो तरफा रणनीति अपनाई है। एक तरफ उसका मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है, और दूसरी तरफ वह पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के लिए फंड जुटाना चाहती है।

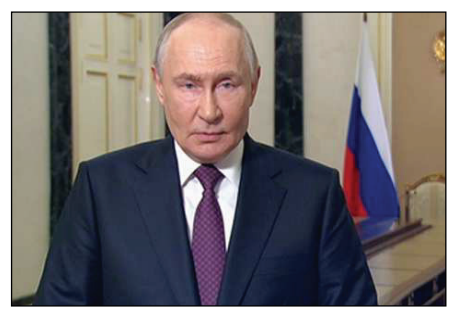

रूस और चीन के बीच संबंध अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुके हैं : पुतिन

मास्को (एजेंसी)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस और चीन के बीच संबंध अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुके हैं और दोनों देश एक-दूसरे की संप्रभुता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर समर्थन देने के लिए तैयार हैं। व्लादीमिर पुतिन ने बीजिंग यात्रा से पहले एक वीडियो संदेश में कहा, चीन दौरे को लेकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरे लंबे समय के अच्छे मित्र और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर मैं ये यात्रा कर पा रहा हूं। रूसी राष्ट्रपति के अनुसार, रूस और चीन के शीर्ष स्तर पर नियमित बातचीत दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने और उनके व्यापक सहयोग को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि 25 साल पहले हुए अच्छे पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण सहयोग संधि ने दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी थी।

बिना रजिस्ट्रेशन बुकिंग खोलना बिल्डर को पड़ा भारीः रेरा ने लैंडक्राफ्ट होम्स पर ठोका जुर्माना

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ-RERA) ने बिना अनिवार्य पंजीकरण के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च करने और आम जनता से बुकिंग राशि वसूलने वाले प्रमोटरों के खिलाफ एक बार फिर सख्त रुख अख्तियार किया है। अथॉरिटी की चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने एक साथ 5 शिकायतों के बैच पर संयुक्त फैसला सुनाते हुए प्रमोटर लैंडक्राफ्ट होम्स एलएलपी को रेरा अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन का दोषी माना है। रेरा ने प्रमोटर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही सभी आवंटियों को उनकी जमा राशि तुरंत वापस करने के आदेश दिए हैं। यह मामला बलराम मीणा, सीमा चौधरी, उमेश कुमार, राजेंद्र कुमार और गर्वित चोपड़ा द्वारा दायर अलग-अलग शिकायतों से जुड़ा है। इन आवंटियों ने प्रमोटर के प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक कराए थे और बुकिंग के एवज में लाखों रुपये का भुगतान किया था। विवाद तब खड़ा हुआ जब प्रमोटर ने न तो समय पर अलॉटमेंट लेटर जारी किए और न ही रेरा नियमों के तहत एग्रीमेंट फॉर सेल (ATS) निष्पादित किया। जब खरीदारों को पता चला कि प्रोजेक्ट का रेरा में कोई वैध पंजीकरण ही नहीं था। तो उन्होंने न्याय के लिए अथॉरिटी का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान यह तथ्य पूरी तरह प्रमाणित हो गया कि प्रमोटर ने प्रोजेक्ट का रेरा पंजीकरण होने से पहले ही उसकी धड़ल्ले से मार्केटिंग की।

सघन नाकाबंदी *राजस्थान पुलिस की सघन नाकाबंदी से अपराधियों में हड़कंप*

810 नाकाबंदी पॉइंट्स पर 47 हजार से ज्यादा वाहनों की जांच

जयपुर(नि.सं.)। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेशभर में चलाए गए दो दिवसीय सघन नाकाबंदी अभियान ने अपराधियों, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों और असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा दिया। इस विशेष अभियान के दौरान कुल 810 नाकाबंदी पॉइंट्स लगाकर 47 हजार से अधिक वाहनों की जांच की गई, जबकि विभिन्न धाराओं में 274 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था श्री वी के सिंह ने बताया कि शनिवार 16 मई को शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक भरतपुर, उदयपुर व कोटा रेंजों में तथा रविवार 17 मई प्रातः 3 से लेकर 6 तक को बीकानेर, जोधपुर व जयपुर रेंजों के सभी प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग की गई। अभियान के तहत पुलिस ने दोपहिया और चौपहिया वाहनों की व्यापक जांच करते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेशभर में कुल 24,573 दोपहिया और 22,531 चौपहिया वाहनों की जांच की गई।

11 हजार से ज्यादा एमवी एक्ट कार्रवाई

नाकाबंदी अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने, फर्जी या बिना नंबर प्लेट और काली फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई। पुलिस ने कुल 11,504 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की। इनमें 757 शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर, 1667 बिना हेलमेट चालकों पर, 1484 बिना सीट बेल्ट, 191 मोबाइल पर बात करते वाहन चालक, 1438 संदिग्ध या बिना नंबर प्लेट वाले वाहन तथा 1017 काली फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शामिल रही।

नाकाबंदी अभियान में उदयपुर रेंज सबसे सक्रिय रही, जहां 2647 एमवी एक्ट कार्रवाई की गई। जबकि अजमेर रेंज में 2576 कार्रवाई दर्ज हुई। जयपुर रेंज में 1795, कोटा में 1768, भरतपुर रेंज में 1735, जोधपुर रेंज में 968 और बीकानेर रेंज में 15 कार्रवाई कर नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसा गया।

ईंधन पर वैश्विक संकट का साया, पूर्व सीएम गहलोत बोले-जोधपुर में 40% पंप 'ड्राई', सिर्फ 1000 का दे रहे तेल

लोक टुडे। जयपुर

राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस (एलपीजी) की स्थिति लगातार संवेदनशील और तनावपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ जहां वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के कारण ईंधन की कीमतों में भारी उछाल आया है, वहीं दूसरी तरफ तेल कंपनियों द्वारा डिपो से की जा रही सीमित आपूर्ति ने प्रदेश में सप्लाई का बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। कई जिलों में स्थिति 'अघोषित रैशनिंग' जैसी हो गई है, जहां उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में ही तेल दिया जा रहा है।

पूर्व सीएम ने सरकार को घेरा :

इस गंभीर स्थिति पर गहरा रोष जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में गहलोत ने दावा किया कि उनके

गृह जिले जोधपुर समेत पूरे प्रदेश में हालात बेहद डरावने हैं। गहलोत ने कहा, 'कल मेरे आवास पर जोधपुर से मिलने आए कई आगंतुकों ने बताया कि वहां पेट्रोल पंपों पर सीमित मात्रा में ईंधन दिया जा रहा है और कई पंप तो पूरी तरह सूख (ड्राई) चुके हैं।

जोधपुर से जयपुर (करीब 350 किमी) आने वाले मुसाफिरों को रास्ते में 3 से 4 बार तेल भरवाना पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल पंप संचालक एक गाड़ी में 1000 से अधिक का फ्यूल डाल ही नहीं रहे हैं '। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केवल पेट्रोल-डीजल ही नहीं, बल्कि आम जनता को कई-कई दिनों तक एलपीजी सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहे हैं।

ये संकट की घड़ी, डीलर्स एसोसिएशन भी चिंतित :

राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार तेल कंपनियों ने निजी कंपनियों के दाम बढ़ाने के बाद सरकारी पंपों पर बढ़े दबाव को देखते हुए सप्लाई पर 'अघोषित कोटा' लागू कर दिया है।

इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्र (इंडस्ट्रीज) पर सरचार्ज लगने के बाद कारखानों ने सीधे रिटेल पंपों से भारी मात्रा में डीजल खरीदना शुरू कर दिया है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए तेल कम पड़ रहा है। पंप संचालकों को कानून-व्यवस्था बिगड़ने का डर सता रहा है।

सरकार का देश में पर्याप्त स्टॉक का दावा :

किल्लत की खबरों के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा तेल विपणन कंपनियों ने आधिकारिक बयान जारी कर जनता से पैनिक न होने की अपील की है। तेल कंपनियों के अधिकारियों के मुताबिक, देश और राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का सरप्लस (अतिरिक्त) स्टॉक मौजूद है। आपूर्ति में कोई तकनीकी या लॉजिस्टिक कमी नहीं है। तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कीमतों में और बढ़ोतरी की आशंका के चलते अवैध भंडारण (जमाखोरी) करने की शिकायतें मिल रही थीं। इस जमाखोरी को रोकने और सभी आम उपभोक्ताओं को समान रूप से ईंधन उपलब्ध कराने के लिए कुछ रिटेल काउंटर्स पर राशनिंग की व्यवस्था लागू की गई है।

राशि वितरण समारोह — विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिभावान विद्यार्थियों का बढ़ाया उत्साह, शिक्षा के लिए दिया प्रोत्साहन

सीमित संसाधन प्रतिभा की राह में बाधा नहीं,जनभागीदारी से निखरेंगी प्रतिभाएं, राष्ट्र निर्माण में निभाएंगी भूमिकाःदेवनानी

■ सिंधी शिक्षा विकास समिति का सराहनीय प्रयास, विद्यार्थियों को मिला शिक्षा संबल

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रतिभा कभी भी सीमित संसाधनों की मोहताज नहीं होती। आवश्यकता केवल उचित मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और अवसर की होती है। जब समाज जनभागीदारी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करता है, तब प्रतिभाशाली बच्चे आगे बढ़कर देश और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे सिंधी शिक्षा विकास समिति अजमेर द्वारा आदर्श विद्या निकेतन विद्यालय में आयोजित प्रतिभावान एवं जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को नकद प्रोत्साहन राशि वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में लगभग 300 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर उनकी शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए सहयोग दिया गया।

सिंधी शिक्षा विकास समिति, अजमेर के संरक्षक एवं विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि शिक्षा रोजगार का माध्यम होने के साथ संस्कार, व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण का आधार है। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासित, संस्कारवान एवं लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर परिश्रम करने वाले विद्यार्थी ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के सक्षम वर्ग को आगे आकर शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना चाहिए ताकि कोई भी प्रतिभा संसाधनों के अभाव में पीछे नहीं रह जाए। उन्होंने बताया कि सिंधी शिक्षा विकास समिति विगत 20 वर्षों से समाज के बच्चों के शैक्षिक उत्थान के लिए सतत कार्य कर रही है। संस्था द्वारा विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य सामग्री, स्कूल बैग, यूनिफर्म, स्वेटर तथा विद्यालय शुल्क सहित विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके सकारात्मक परिणामस्वरूप समाज के अनेक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल कर रहे हैं। देवनानी ने कहा कि आज के विद्यार्थी ही कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। यदि बच्चों को सही दिशा, संस्कार और अवसर मिलते हैं तो वे समाज एवं राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों को भी जीवन में अपनाने का आह्वान किया। पूर्व पार्षद श्री रमेश चेलानी ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि सिंधी शिक्षा विकास समिति सामाजिक सरोकारों के तहत विभिन्न अवसरों पर बच्चों के बीच मिठाई एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी करती है।

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का हुआ आयोजन

केंद्र एवं राज्य सरकारी की लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर हुई चर्चा

जयपुर(नि.सं.)। जयपुर जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन हुआ। जयपुर ग्रामीण सांसद श्री राव राजेन्द्र सिंह, जयपुर सांसद श्रीमती मंजू शर्मा, दौसा सांसद श्री मुरारीलाल मीणा एवं सीकर सांसद श्री अमराराम की मौजूदगी में आयोजित हुई बैठक में जिले में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सहित जनहित से जुड़े अहम् बिन्दुओं पर चर्चा हुई। जयपुर सांसद ने कहा कि पेयजल आम आदमी की मूलभूत आवश्यकता है। गर्मी के मौसम को देखते हुए जयपुर शहर में पेयजल की माकूल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जलदाय विभाग को दिए हैं। उन्होंने आगामी 15 दिवस में जयपुर जिले में बेहतर पेयजल व्यवस्था हेतु स्वीकृत एमपी एमएलए लेड के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रदान किए हैं। उन्होंने एक सप्ताह उपरांत जयपुर जिले की पेयजल समस्याओं के निराकरण के संबंध में पुनः बैठक आयोजित करने के निर्देश जिला कलक्टर जयपुर को दिए। उन्होंने मानसून से पूर्व शहर के सभी नाले-नालियों की सफाई प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए हैं ताकि वर्षा के दौरान जलभराव के कारण आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को इसका लाभ प्रदान कराने के लिए वार्ड अनुसार शिविर लगाकर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने जयपुर के मध्य से गुजरने वाली द्रव्यवती नदी का उचित विकास व सौंदर्यीकरण कराकर उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

न्यूज़ इन बॉक्स

अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने की बजट घोषणाओं सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश

जयपुर(नि.सं.)। अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, निदेशालय विशेष योग्यजन, अनुजा निगम एवं बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट घोषणाओं सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर प्रगति की जानकारी ली। कुमार ने सचिवालय स्थित अपने कक्ष में बैठक लेते हुए वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की मुख्यमंत्री बजट घोषणा, स्कैमेटिक बजट, एसएनए-स्पर्श, भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि, राजकाज पर लंबित पत्रावलियाँ, लंबित विधानसभा प्रश्न, मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति, भूमि आंवटन संबंधित मुद्दे सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

जयपुर में एक पंप पर डीजल का स्टॉक खत्म

दूसरी जगह सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल बेचा जा रहा; जोधपुर में लाइनें लगीं, उदयपुर-टोंक में दो पंप बंद हुए

जयपुर (नि.सं.)। पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के साथ राजस्थान में इनकी कमी का असर भी दिखने लगा है। जयपुर के गोपालपुरा बाईपास स्थित पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं मिल रहा है। पंप सुपरवाइजर का भी कहना है कि डीजल की सप्लाई लगातार कम हो रही है। वहीं, रिद्धि-सिद्धि चौराहे स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर केवल प्रीमियम पेट्रोल ही उपलब्ध कराया जा रहा है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि सामान्य पेट्रोल की सप्लाई बेहद कम हो गई है। इसी तरह राज्य के अलग-अलग जिलों में पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों का असर दिखा। जोधपुर में पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें लगी नजर आई। उदयपुर और टोंक में दो पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं।

गायत्री राठौड़ ने जोधपुर में चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा की

भीषण गर्मी में मरीजों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

जयपुर(नि.सं.)। चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने सोमवार को डॉ. सम्पूर्णानन्द मेडिकल कॉलेज सभागार, जोधपुर में चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, मानव संसाधन, आधारभूत संरचना, निर्माण कार्यों एवं चिकित्सा संसाधनों की विस्तृत समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। बैठक में प्रिंसिपल एवं कंट्रोलर बी.एस. जोधा ने मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पतालों की व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। स्वीकृत एवं कार्यरत पदों के विवरण, संबद्ध

अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों एवं नर्सिंग अधिकारियों की स्थिति, ओपीडी एवं आईपीडी में मरीजों की संख्या, उपलब्ध बेड क्षमता, ऑपरेशन थिएटरों की संख्या, चल रहे निर्माण कार्यों, बजट घोषणाओं की प्रगति, चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता तथा दवाइयों की स्थिति से अवगत कराया गया।

भीषण गर्मी में मरीजों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश

गायत्री राठौड़ ने निर्देश दिए कि वर्तमान भीषण गर्मी को देखते हुए अस्पतालों में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए पर्याप्त छायादार स्थान, पेयजल, बैठने एवं शीतलन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के उपचार एवं सुविधा प्रबंधन पर ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में वृद्ध मरीजों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाए।

फर्जी ट्रांसफर आदेश

स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग-अधिकारी ने अपना फर्जी ट्रांसफर आदेश दिया

निदेशक के नाम से फर्जी ऑर्डर में कोटपूतली विधायक की अनुशंसा का जिक्र भी, मामला दर्ज

जयपुर(नि.सं.)। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में एक कर्मचारी ने खुद का ही फर्जी तबादला आदेश जारी कर दिया। मामले में नर्सिंग अधिकारी दिलीप सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपना तबादला सिरोही से कोटपुतली-बहरोड़ करवाने के लिए फर्जी आदेश तैयार किए। आरोपी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान के निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा के नाम से फर्जी ट्रांसफर आदेश जारी किए। इस ऑर्डर में डॉ. रवि प्रकाश के अधिकृत हस्ताक्षरों का उपयोग कर आदेश को वास्तविक दिखाने का प्रयास किया गया। यह जारी लेटर 24 अप्रैल 2026 को जारी किया गया। फर्जी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल की अनुशंसा और विभागीय आवश्यकता के आधार पर यह तबादला किया जा रहा है। निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने सोमवार को अशोक नगर थाने में मामला दर्ज कराया।

निदेशक ने मामला कराया दर्ज

मामले का खुलासा होने पर जन स्वास्थ्य के निदेशक ने जयपुर के अशोक नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसमें फर्जी दस्तावेज तैयार करने, सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और विभाग को गुमराह करने के आरोप लगाए गए हैं।

रणथंभौर टाइगर रिजर्व से माही समेत दो बाघिन लापता

फॉरेस्ट विभाग ने 100 ट्रैप कैमरे लगाए, पांच टीमें कर रही सर्च

सवाई माधोपुर (वि.सं.)। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से दो बाघिन लापता हो गई। आरबीटी-2504 (माही) और आरबीटी-2510 कई दिनों से नजर नहीं आ रही हैं, जिसके बाद वन विभाग ने सघन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दोनों बाघिनों की तलाश के लिए पांच टीमें लगातार जंगल में पैदल पेट्रोलिंग कर रही हैं और करीब 100 कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं।

मां से टेरिटोरियल फाइट के बाद 'माही' लापता

डीएफओ मानस सिंह ने बताया - बाघिन टी-124 रिद्धि की बेटी आरबीटी-2504 (माही) और उसकी मां के बीच कई बार टेरिटोरियल फाइट हो चुकी है। 3 मई को भी दोनों के बीच टेरिटोरियल संघर्ष हुआ था, जिसके बाद से माही नजर नहीं आ रही है।

राजस्थान पुलिस ने बताया जीआरएम मॉड्यूल का आसान तरीका

अब खाताधारकों को नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, ऑनलाइन होगी शिकायत से समाधान तक पूरी प्रक्रिया

साइबर ठगी में फ्रीज बैंक खातों से मिलेगी राहत

जयपुर(नि.सं.)। साइबर धोखाधड़ी के मामलों में जांच के दौरान फ्रीज किए जाने वाले बैंक खातों से परेशान आमजन के लिए अब बड़ी राहत की खबर है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (IyC) द्वारा विकसित जीआरएम (ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म) मॉड्यूल अब ऐसे खाताधारकों के लिए प्रभावी और पारदर्शी समाधान बनकर उभरा है, जिनके बैंक खाते साइबर जांच के दौरान संदिग्ध ट्रांजेक्शन के कारण फ्रीज, लियन या होल्ड कर दिए जाते हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम श्री वी. के. सिंह ने बताया कि राज्य में साइबर अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों को त्वरित राहत देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में लागू किया गया जीआरएम मॉड्यूल आमजन के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। पहले ऐसे मामलों में खाताधारकों को पुलिस, बैंक और विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और जवाबदेह तरीके से संचालित की जा रही है।

क्या है जीआरएम मॉड्यूल

जीआरएम मॉड्यूल एक ऑनलाइन शिकायत

निवारण प्रणाली है, जो नेशनल साइबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) और सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS) के अंतर्गत कार्य करती है। इसका उद्देश्य साइबर अपराध जांच के दौरान फ्रीज या लियन किए गए बैंक खातों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक खाताधारकों को राहत उपलब्ध कराना है।

ऐसे काम करता है जीआरएम मॉड्यूल

जीआरएम प्रक्रिया के तहत खाताधारक सबसे पहले अपनी बैंक शाखा में जाकर खाते को अनफ्रीज करवाने या लियन हटाने के लिए आवेदन करता है। इसके बाद बैंक संबंधित व्यक्ति की केवाईसी और ट्रांजेक्शन का सत्यापन करता है।

ईडी अधिकारी बनकर डराया, 13.75 लाख ठगे

फर्जी FIR और बैंक स्टेटमेंट भेजा, बोले-आंतकवादियों को फंडिंग करते हो

पाली(वि.सं.)। ईडी अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने पहले आतंकवादी गतिविधियों में फंडिंग करने का आरोप लगाया, फिर गिरफ्तारी और जेल भेजने की धमकी देकर 13.75 लाख रुपए ठग लिए। वीडियो कॉल पर फर्जी एफआईआर और बैंक स्टेटमेंट भेजकर इतना डराया गया कि पीड़ित ने अपने बैंक खातों और एफडी की रकम आरोपियों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दी। इसके बाद भी आरोपी लगातार और रुपए जमा कराने का दबाव बनाते रहे। मामला पाली जिले के रानी थाना क्षेत्र के बिजोवा गांव का है, जहां 63 साल नारायण सिंह साइबर ठगी का शिकार हो गए। आखिर एक दोस्त की सलाह पर उन्होंने साइबर थाने में 7 मई को रिपोर्ट दर्ज करवाई।

[illegible]